

## न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:- 30/05 (RCMS No.2005/00005) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. बृजेन्द्र सिंह पुत्र बस्ती लाल मृतक

1/1. यादराम

1/2. गोविन्द सिंह

1/3. ओमसिंह

1/4. भगवान सिंह

1/5. प्रेम सिंह

पिसरान बृजेन्द्र जाति जाट निवासी जघीना तहसील व जिला  
भरतपुर

.....अपीलान्त

बनाम

1. लक्ष्मन सिंह

2. रामवीर

3. ओमप्रकाश

4. श्याम सिंह (मृतक)

4/1. रामश्री पत्नि श्याम सिंह जाति जाट

4/2. करतार पुत्र श्याम सिंह

4/3. सुरेश पुत्र श्याम सिंह

पुत्रान गोविन्द सिंह जाति जाट निवासी जघीना तहसील व जिला  
भरतपुर

जाति जाट निवासी जघीना तहसील व  
जिला भरतपुर

..... रैसपो

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार भरतपुर दिनांक

16.10.2003

सत्यमेव जयते

उपस्थिति:-

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलान्त

2. श्री लक्ष्मन सिंह वकील रैसपो

निर्णय दिनांक:-05.07.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.10.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि श्याम सिंह पुत्र बस्तीलाल ने विवादित आराजी ख0 नं0 8617 रकवा 0.44, 8617/10717 रकवा 0.09

किता 2 रकवा 0.53 का 1/2 हिस्सा एवं ख0 नं0 8618 रकवा 0.46 सालिम वांके ग्राम जघीना नं0 4 तहसील व जिला भरतपुर का रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 28.04.97 से लक्षमन सिंह, रामवीर सिंह, ओमप्रकाश पिसरान गोविन्द सिंह जाति जाट को बिक्रय कर दिया। वयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 180 सरपंच ग्राम पंचायत जघीना द्वारा दिनांक 30.04.97 को तस्दीक कर दिया। इस नामान्तरकरण आदेश के विरुद्ध बृजेन्द्र सिंह पुत्र बस्ती लाल ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देशके साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि वह दोनों पक्षों को सुनकर दाखिल खारिज के संबंध में पुनः निर्णित करें। इस आदेश के विरुद्ध क्रेतागण लक्षमण सिंह वगैरहा ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में अपील पेश की। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय को यथावत रखा। प्रकरण रिमाण्ड आदेश के क्रम में तहसीलदार भरतपुर ने उभय पक्ष को सुनकर नामान्तरकरण सं0 180 निर्णय दिनांक 30.04.97 को अपने निर्णय दिनांक 16.10.03 से यथावत रखा। इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों ने लिखित बहस पेश की।

विद्वान वकील अपीलान्त ने लिखित बहस में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त की ओर से इकरारनामा दिनांक 24.11.94 एवं जबाब दावा श्याम सिंह दिनांक 05.09.98 की प्रतियां पेशकी गई हैं जिनमें श्याम सिंह ने तथाकथित विक्रय पत्र बहक रैस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 दिनांक 21.04.97 के विपरीत विवादित आराजी पर अपीलान्त का कब्जा होना स्वीकार किया है। जिसका कोई खण्डन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं हुआ है। तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 21.04.97 के आधार पर कोई कब्जा नहीं दिया गया है। प्रथम तो स्वयं विक्रेता ने अपीलान्त के हक में लिखे गये इकरारनामा में स्वीकार किया है, दूसरे उत्तरवादी सं0 1 लगायत 3 ने भी इकरारनामा दिनांक 10.06.97 में स्वीकार किया है कि 2 वर्ष के अन्दर रकम चुकती होने पर रजिस्ट्री वापिस श्याम सिंह को कर दी जावेगी। भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 133 सी के अनुसार रजिस्ट्री डीड के तहत कब्जे का हस्तान्तरण होना आवश्यक है। इस मामले में कब्जा प्रमाणित नहीं है। क्रेतागण अजनवी क्रेता है। उनके द्वारा अविभाजित हिस्साक्य कियाजाना बताया है। इस प्रकार से भी कब्जा होना साबित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में 1996 आरआरडी 148 एल.बी. उदृत की। उन्होंने लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत दावे में रैस्पो0 सं0 4 ने अपीलान्त के हक में इकरारनामा होना स्वीकार किया है। इकरारनामा के संबंध में नियमित वाद बृजेन्द्र सिंह बनाम श्याम सिंह सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए दाखिल खारिज की कार्यवाही को न्यायहित में स्थगित कियाजाना जरूरी है। अपने पक्ष के समर्थन में 1995 आरबीजे 55, 1989 आरआरडी 224, 1992 आरआरडी 304, 1985 आरआरडी 175 का हवाला दिया। अधीनस्थ न्यायालय में कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य दर्ज नहीं की है, न ही साक्षियों के बयानलिये गये हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार भरतपुर का आदेश दिनांक 16.10.03 निरस्त की जावे।

विद्वान वकील रैसपो० ने लिखित बहस में अंकित किया है कि अपीलान्त बृजेन्द्र सिंह व रैसपो०श्याम सिंह एक ही पिता बस्ती लाल की संतान है, जो खास भाई हैं। श्याम सिंह विवादित आराजी का खातेदार रहा है उसे अपनी आराजी को बिक्रय करने का अधिकार रहा है। उसी अधिकार के तहत श्याम सिंह ने विवादित आराजी को रैसपो० सं० 1 लगायत 3 लक्षमन सिंह वगैरहा को बेचान कर दिया व मौके पर कब्जा दे दिया। वयनामा के आधार पर तहसीलदार द्वारा मौके की जाँच कराकर राजस्व रिकार्ड में रैसपो० श्याम सिंह के स्थान पर रैसपो० सं० 1 लगायत 3 के हक में नामा० का अमल करा दिया। इस नामा० के विरुद्ध अपीलान्त ने पूर्व में अपील की थी। अपील रिमाण्ड होने पर तहसीलदार भरतपुर ने मौकेका निरीक्षण किया, कब्जा क्रेतागण कापाया। अपीलान्त ने इसअपील के अलावा विक्रयपत्र को सिविल न्यायालय भरतपुर मे चलेन्ज कर दावा बृजेन्द्र बनाम लक्ष्मन पेश किया। उसमें भी वही आधार लिये गये जो मौजूद अपील में लिये गये हैं। सिविल न्यायालय द्वारा अपीलान्त का दावा खारिज कर दिया। जिसकी प्रति संलग्न की है। बिक्रय पत्र को विधि अनुसार माना व कब्जा रैसपो०का माना। इस सिविल न्यायालय के निर्णय की कोई अपील अपीलान्त ने नहीं की है। सिविल न्यायालय कानिर्णय अंतिम हो चुका है। सिविल न्यायालय के निर्णय व डिक्री से अपीलान्त पाबन्द है। इसलिये यह अपील मैन्टेनैविल नहीं हैं। अपीलान्त रैसपो० श्याम सिंह का वारिस नहीं है और न ही अपीलान्त ने यह कहा है कि रैसपो० श्याम सिंह को बिक्रय करने का अधिकार नहीं है। उक्त विक्रय पत्र को श्याम सिंह ने या उनके वारिसान ने चलेन्ज नहीं किया है। अपीलान्त को नामान्तरकरण चलेन्ज करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त को ज्यादा से ज्यादा विभाजन का दावा लाने का अधिकार ही प्राप्त है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख० नं० 8617 रकवा 0.44, 8617/10717 रकवा 0.09 किता 2 रकवा 0.53 का 1/2 हिस्सा एवं ख० नं० 8618 रकवा 0.46 सालिम वांके ग्राम जघीना नं० 4 तहसील व जिला भरतपुर का श्याम सिंह पुत्र बस्तीलाल खातेदार था। उसने दिनांक 28.04.97 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा रैसपो० 1 लगायत 3 लक्षमन सिंह, रामवीर सिंह, ओमप्रकाश पिसरान गोविन्द सिंह जाति जाट को बिक्रय कर दिया। वयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 180 दिनांक 30.04.97 को दर्ज किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध बृजेन्द्र सिंह ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की, जो आंशिक रूप से स्वीकार कर, प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को पुनः निर्णय के लिये प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध लक्ष्मण सिंह वगैरहा ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी, जो खारिज हो गयी। रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार भरतपुर ने दोनों पक्षों को सुनकर नामान्तरकरण सं० 180 ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.97 को अपने निर्णय दिनांक 16.10.03 से यथावत रखा। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी से संबंधित प्रकरण सिविल न्यायालय में नियमित वाद बृजेन्द्र सिंह बनाम श्याम सिंह विचाराधीन था जिसका निर्णय 26.04.10 को हो चुका है। जैसाकि रैसपो० द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित नकल उनवानी बृजेन्द्र सिंह बनाम श्याम सिंह वगैरहा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) संख्या तीन भरतपुर से जाहिर है। माननीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी ख० नं० 8617 रकवा 0.44, 8617/10717 रकवा 0.09 किता 2 रकवा 0.53 का 1/2 हिस्सा

के संबंध में अपीलान्त मृतक बृजेन्द्र सिंह का दावा खारिज किया है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रकरण पुनः निर्णय के लिये तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.10.2003 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.04.2010 के परिपेक्ष्य में निर्णय के लिये रिमाण्ड किया जाता है। पक्षकार तहसीलदार भरतपुर के न्यायालय में दिनांक 06.08.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official